AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National

ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

लोहरा समुदाय पर कई जनजातीय विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन

वीणा कुमारी

पीएच.डी

स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग राँची विश्वविद्यालय, राँची

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATIONIN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.IHAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL

सारांश

भारत में जनजातीय आबादी, हालांकि संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक है, समूहों की एक विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। वे भाषा और भाषाई लक्षणों, पारिस्थितिक सेटिंग्स जिसमें वे रहते हैं, भौतिक सुविधाओं, जनसंख्या का आकार, संस्कृति–संक्रमण की सीमा, आजीविका बनाने के प्रमुख तरीके, विकास का स्तर और सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में आपस में भिन्न होते हैं। वे देश की लंबाई और चौड़ाई में भी फैले हुए हैं, हालांकि उनका भौगोलिक वितरण एक समान नहीं है। राज्य में आदिवासियों की बड़ी आबादी विकासात्मक हस्तक्षेप के संदर्भ को परिभाषित करने वाली सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों के संदर्भ में महत्व रखती है। कार्य–भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि के संदर्भ में उनकी वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के साथ–साथ राज्य में अनुसूचित जनजाति के भेद्यता और लंबे समय तक हाशिए पर रहने का इतिहास राज्य द्वारा किए गए सभी विकासात्मक गतिविधियों में उनके समावेश और लक्ष्यीकरण को रोकता है। प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के लिए आवश्यक आँकड़े प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित किये गये हैं। वर्तमान अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड, इंटरऑपरेशन और जनमत के माध्यम से कार्य की प्रस्तुति के लिए I-T-D-A- के प्रत्येक प्रभाग की गहन जांच की जाती है।

कीवर्ड: *– विकास और सामाजिक, सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं, जनजातीय जनसंख्या।*

परिचय

'जनजाति' या 'आदिवासी' शब्द हमारे दिमाग में आधे नग्न पुरुषों और महिलाओं की तस्वीर लाता है, जिनके हाथों में तीर और भाले होते हैं, उनके सिर में पंख होते हैं, एक अस्पष्ट भाषा बोलते हैं, उनका

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National
ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

जीवन अक्सर मिथकों से जुड़ा होता है जंगलीपन और नरभक्षण। हालांकि, आदिवासी गांव का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति एक समुदाय को प्रकृति के करीब, शांतिप्रिय, न्यायसंगत और उन्नत सांस्कृतिक ध सामाजिक रूपों के साथ देखकर आश्चर्यचकित और रोमांचित होगा। आदिवासियों के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, जो हमें उनकी गरिमा की कीमत पर कई मिथकों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। यहां तक कि जब दुनिया में बहुसंख्यक समुदाय अपनी जीवन–शैली बदलते रहे, एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहे और दुनिया की 'प्रगति' के साथ तालमेल बिठाने के लिए भौतिकवादी प्रवृत्ति विकसित की, तब भी ऐसे समुदाय थे जो अपने पारंपरिक मूल्यों, रीति–रिवाजों और विश्वास। मुख्यधारा के समाज की शोषक मानसिकता ने इन समुदायों को अक्सर जंगलों और उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ों में पीछे छोड़ दिया, जहां वे प्रकृति और उनके प्रदूषण रहित परिवेश के साथ शांति से रहना जारी रख सके। जैसा कि मुख्यधारा के समाज के तथाकथित सभ्य समुदाय न तो इन समुदायों के मूल्यों और आदर्शों को समझसकते थे और न ही उनकी जीवन शैली को समझने का धैर्य रखते थे, मुख्यधारा की दुनिया ने उन्हें मूल निवासी, असभ्य लोग, आदिवासी, आदिवासीध गिरिजन के रूप में विभिन्न प्रकार से ब्रांड किया।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) अपने मिथकों और रीति–रिवाजों में अन्य जाति, भाषा, संस्कृति और मान्यताओं से काफी भिन्न है। समूह 105 भाषाओं और 225 सहायक भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आदिवासियों द्वारा बसाए गए क्षेत्र देश के अल्प–विकसित क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आदिवासी ज्यादातर अलग–थलग गांवों या बस्तियों में रहते हैं। उनकी आबादी का एक छोटा हिस्सा अब स्थायी गांवों के साथ–साथ कस्बों और शहरों में भी बस गया है। 'द ट्राइब' मानव समाज में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसे मानव समाज के विकास में एक प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है।

भारत में जनजातीय समुदायों को चार बोर्ड श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी में सुदूर, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजातियाँ शामिल हैं और कृषि–पूर्व व्यवसाय जैसे कि भोजन एकत्र करना, फल एकत्र करना, शिकार करना और मछली पकड़ना। दूसरी श्रेणी में वे जनजातियाँ शामिल हैं जो झूम खेती करती हैं और बाहरी दुनिया से उनके संपर्क के कारण कुछ अधिक उन्नत मानी जाती हैं। तीसरी श्रेणी में वे जनजातियाँ आती हैं जिन्हें संक्रमण काल में माना जा सकता है। वे आंशिक रूप से परसंस्कृत हैं, बसी हुई खेती के बाद और विकास की पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

रूपांतरण की परिघटनाओं को विभिन्न प्रकार से वर्णित किया गया है जैसे आत्मसातीकरण, परसंस्कृतिकरण, एकीकरण, कृषकीकरण, विजातीयकरण, पुनःआदिवासीकरण, आदि। परिवर्तन की प्रकृति और सीमा एक जनजातीय समुदाय से दूसरे जनजातीय समुदाय में भिन्न होती है, जो कई कारकों पर निर्भर

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National
ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

करती है जैसे कि अन्य के साथ जुड़ाव या संपर्क की डिग्री समुदायों, विकासात्मक कार्यक्रमों तक पहुंच और विकास प्रक्रिया में भागीदारी की सीमा। आदिवासियों के बीच मानव विकास का विश्लेषण करने से पहले जनजाति की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा और जनजातियों के मानव विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

- **आदिवासियों के लिए सरकारी उपाय**

आदिवासियों की दुर्दशा को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि, सिंचाई, पशुपालन, गृहस्थल, सहकारी ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवश्यक वस्तुओं का वितरण आदि को कवर करना है। इनका उद्देश्य आदिवासियों को एक कानूनी ढांचा प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करना भी है, और उनके विकास को सुव्यवस्थित करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। उनके विकास के मुख्य साधन के रूप में काम करने के लिए, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय उप–योजनाएँ तैयार और कार्यान्वित की गई हैं। वे राज्य योजना, विशेष केंद्रीय सहायता, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और संस्थागत वित्त से जुड़े हुए हैं।

उद्देश्यों

1. मानव संसाधन का विकास और शिक्षा का उन्नयन।
2. भूधृति, साहूकार, ऋण बंधन, व्यापार, आबकारी, वन श्रम आदि के क्षेत्र में आदिवासियों के शोषण का उन्मूलन।

साहित्य की समीक्षा

निलोय सरकार और तातिनी नाथ (2016) ने भारत के त्रिपुरा राज्य में बसे 19 जनजातियों की स्वास्थ्य स्थिति को विकसित करने के लिए रणनीतियों का विश्लेषण किया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को दिखाना और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए रणनीति सुझाना है। अध्ययन अगरतला और धर्म नगर से प्राप्त प्राथमिक और द्वितीयक सूचनाओं पर निर्भर करता है। विश्लेषण के अनुसार प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में डायरिया रोग, परजीवी संक्रमण, संक्रामक हेपेटाइटिस, आंत्र ज्वर और अन्य जलजनित रोग थे और यह देखा गया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, खराब स्वच्छता और खराब माँ और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाएं इसके कुछ कारण हैं। इन बीमारियों के लिए। बच्चों में कुपोषण, खून की कमी, मलेरिया और सांस की बीमारियों की दर अधिक है। यह सब पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा और सेवा प्रदाताओं की अनुपलब्धता, अत्यंत ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य

ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

शिक्षा की अनुपस्थिति, त्रिपुरा की जनजातीय आबादी में कार्यक्रमों की अपर्याप्त योजना और कार्यान्वयन के कारण है।

गौतम कुमार क्षत्रिय (2014) ने भारत में बढ़ती जीवन शैली के रोगों के संदर्भ में जनजातीय स्वास्थ्य के बदलते परिप्रेक्ष्य पर एक सर्वेक्षण किया। सरकारी प्रयासों के बावजूद जनजातीय आबादी अन्य आबादी की तुलना में जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में पिछड़ रही है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम कारकों के साथ उम्र, लिंग और बॉडी मास इंडेक्स के संबंध को समझना है। सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल के बीरूभूम जिले और ओडिशा के मयूरभंज जिले की छह जनजातियों के बीच किया गया था। कुल 1434 उत्तरदाताओं में से 705 पुरुष उत्तरदाता थे और 729 महिला उत्तरदाताओं को 20–60 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित चुना गया है। सर्वेक्षण से यह नोट किया गया है कि ≥40 वर्ष की आयु के पुरुषों की तुलना में ≥40 वर्ष की आयु के पुरुषों में चयापचय जोखिम विकसित होने का खतरा अधिक पाया गया है।

अजीत जायसवाल (2013) ने मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर चर्चा की। कुपोषण और स्वास्थ्य की स्थिति के प्रसार का अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र की भूमिया जनजातियों पर सर्वेक्षण किया गया था। कुल 201 परिवारों में 616 उत्तरदाता शामिल हैं जिनमें 317 पुरुष, 299 महिलाएं और 125 प्री–स्कूल बच्चे हैं। मापे गए सभी उत्तरदाताओं की ऊंचाई और वजन और बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) की गणना की गई और पोषण सेवन की तुलना अनुशंसित आहार भत्तों के साथ की गई और एनसीएचएस डेटा के साथ तुलना की गई। लगभग 58.6: पूर्वस्कूली बच्चे कम वजन के थे, जिनमें से 23.2: बहुत कम वजन के थे। सिफारिश की तुलना में अनाज की खपत अधिक थी और अन्य पोषक तत्वों की खपत बहुत कम है।

श्रीनिवास पत्रुडु एम, चंटी बाबू नायडू जी और पुल्ला राव डी (2013) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर एक अध्ययन किया। शोध में साक्षरता का स्तर, ड्रॉपआउट, ड्रॉपआउट का कारण, शैक्षिक संस्थानों की दूरी और स्वास्थ्य संबंधी विशेषताएं जैसे पेयजल सुविधा, खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के प्रकार, रोगग्रस्त व्यक्ति का लिंग और आयु के अनुसार वर्गीकरण, सरकारी अधिकारियों से स्वास्थ्य सहायता शामिल हैं। एक गाँव में 100 जनजातीय परिवारों के एक नमूने का चयन किया गया और प्राथमिक आँकड़ों के संग्रह के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया। माध्यमिक डेटा मुख्य योजना अधिकारी विशाखापत्तनम से एकत्र किया गया था।

राजकुमार पी, विजयचंद्र रेड्डी और करुणा कुमार डी (2013) ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति की जांच की। विजयनगरम जिले के वेपाड़ा

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National
ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

मंडल के 89 उत्तरदाताओं के एक नमूने पर बहुस्तरीय यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण के लिए विचार किया गया। प्रस्तावित नमूनों की स्वास्थ्य स्थितियों का अध्ययन करने के लिए लिंग और आयुवार वर्गीकरण किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 40: रोगग्रस्त आबादी 6 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में देखी गई थी। एक महिला बच्चों के बगल में आती है। शिक्षा की स्थिति पर अध्ययन से पता चलता है कि महिला निरक्षर 5.62: की तुलना में पुरुष निरक्षर 82.02: के साथ हावी हैं।

मणिकांत पी (2013) ने आंध्र प्रदेश के जनजातीय बुजुर्गों की स्वास्थ्य स्थिति पर एक अध्ययन का पता लगाया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बुजुर्गों की स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन करना और उनके द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं और परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए समर्थन पर चर्चा करना है। अध्ययन नेल्लोर जिले के तीन जनजातीय समूहों यनादी, चित्तूर जिले के येरुकुला और मेदक जिले के सुगली में किया गया था। अध्ययन के लिए प्रत्येक समूह से 50 पुरुषों और 50 महिलाओं पर विचार किया गया है अर्थात 60 वर्ष से अधिक आयु के कुल 300 नमूनों पर विचार किया गया है। कुल उत्तरदाताओं में से 84.3: मामूली या बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं और केवल 15.7: बीमारी से मुक्त थे।

विजया कुमार जी, नागराजू एम और रमनजनेयुलु एम (2014) ने आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति पर एक सर्वेक्षण किया। जनजातियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सरल मात्रात्मक तकनीकों जैसे प्रतिशत, सरल और चक्रवृद्धि विकास दर का उपयोग किया गया। अध्ययन प्रकाशित दस्तावेजों से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा पर आधारित था। पुरुष साक्षरता दर (47.66:) और महिला साक्षरता दर (26.11:) में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन राज्य की अन्य आबादी की तुलना में यह बहुत कम है। राज्य में हैदराबाद जिले में साक्षरता की उच्चतम दर यानी 55. 38: और महबूब नगर में सबसे कम है। आंध्र प्रदेश में जनजातियों के लिए लगभग 152 प्राथमिक विद्यालय, 599 आश्रम विद्यालय, 441 छात्रावास हैं। 50: ड्रॉपआउट चौथी और पांचवीं कक्षा से हैं।

क्रियाविधि

अनुसूचित जनजातियों को चार दशकों से अधिक समय से विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय प्राप्त होते रहे हैं लेकिन वे भारतीय समाज के उन्नत वर्गों के स्तर तक नहीं आ पा रहे हैं।

जनसांख्यिकी प्रोफाइल अधिकांश अनुसूचित जनजातियां अविकसित क्षेत्रों में निवास करती हैं, जो दूर–दराज के इलाकों में हैं जहां आबादी का घनत्व कम है और बुनियादी सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National
ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

है (वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार, 2011)। हालांकि, पिछले पांच दशकों से एसटी आबादी ने सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखी है।

परिणाम और चर्चा

जनजातीय 123 शिक्षा, विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक ताने–बाने और कठिनाइयों के साथ एक विशिष्ट अनुशासन होने के कारण, इससे जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसलिए उनकी अज्ञानता और निरक्षरता के कारण शैक्षिक कार्यक्रम अधिक प्रगति नहीं कर सके। इसलिए, जनजातियों के बीच शिक्षा को उनकी अर्थव्यवस्था और समाज की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाना चाहिए।

- **भारत में साक्षरता दर**

तालिका 1भारत में अनुसूचित जनजातीय समूहों के बीच साक्षरता

क्र.सं.	वर्ष	पुरुष	महिला	कुल
1	1993	44.2	45.2	77.2
2	1995	77.2	55.2	77.5
3	1997	77.2	85.2	85.2

स्रोतः जनगणना, 2011।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National
ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

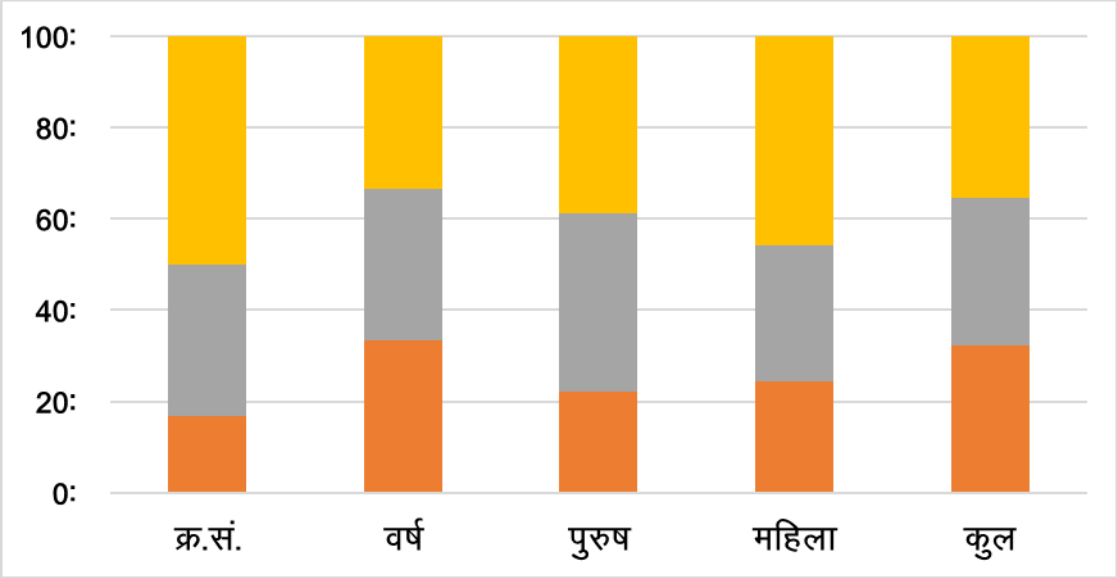

आकृति 1भारत में अनुसूचित जनजातीय समूहों के बीच साक्षरता

आजादी के बाद से जनजातीय साक्षरता में वृद्धि हुई है लेकिन राष्ट्रीय औसत के अनुसार नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में आदिवासियों (0–6 वर्ष की आयु के बच्चों को छोड़कर) के बीच कुल साक्षरता दर 59: है। आदिवासियों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। और पुरुष और महिला प्रतिशत के आधार पर, पुरुष 68.5: और महिलाओं में 49.4: खाते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर 19.1: है और यह शहरी क्षेत्रों (12.9:) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (19.9:) में अधिक है। आदिवासियों के बीच कुल साक्षरता दर लक्षद्वीप (91.7:) में सबसे अधिक है और सबसे कम आंध्र प्रदेश (49.2:) है।

तालिका 2वैवाहिक स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	पडेरू	चिंतापल्ली	मंचिंगपुट	सभी मंडल
1	विवाहित	4	55	25	45
2	अविवाहित	44	12	23	63
3	तलाक	51	11	26	23
4	विधवा	25	46	12	15

स्रोत: जनगणना, 2011।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National
ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

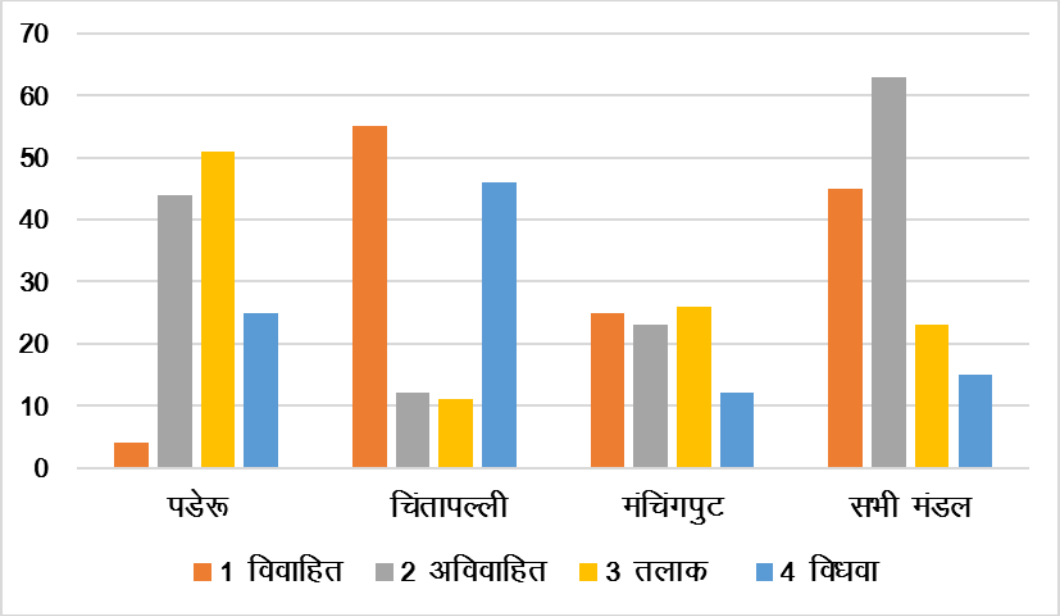

आकृति 2वैवाहिक स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

उपरोक्त तालिका 2 वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में उत्तरदाताओं के वितरण को दर्शाती है। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अविवाहित (4:) की तुलना में कुल उत्तरदाताओं में से 80: से अधिक विवाहित हैं। तलाकशुदा (4.67:) की तुलना में विधवा (8.33:) उत्तरदाता अधिक हैं।

तालिका 3परिवार के प्रकार द्वारा उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	पडेरू	चिंतापल्ली	मंचिंगपुट	सभी मंडल
1	संयुक्त परिवार	4	54	28	45
2	एकल परिवार	44	44	23	63

स्रोत: जनगणना, 2011।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National
ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

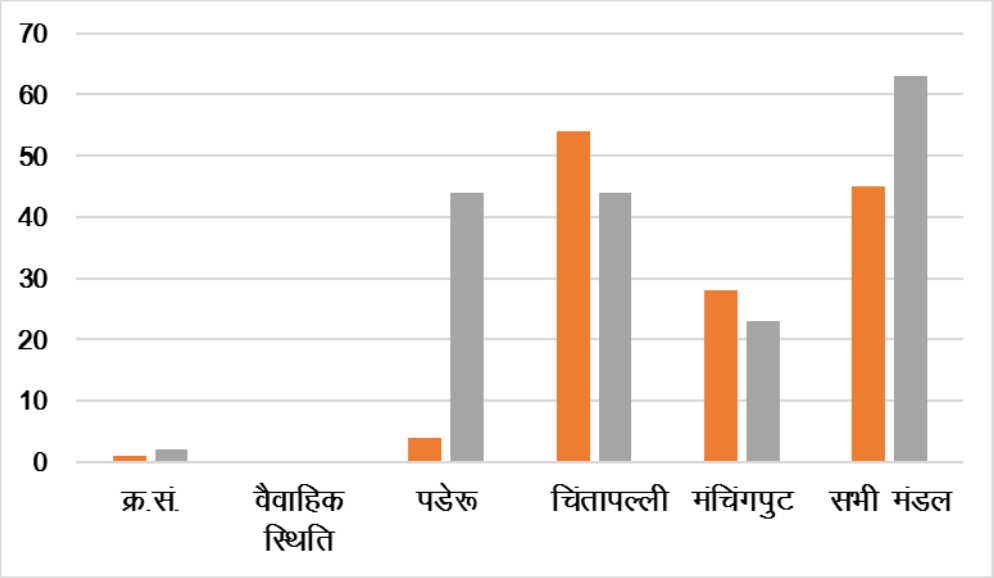

आकृति 3परिवार के प्रकार द्वारा उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

उपरोक्त तालिका 3 परिवार के प्रकार के संदर्भ में उत्तरदाताओं के वितरण को दर्शाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि संयुक्त परिवार (4.33:) की तुलना में लगभग 95: उत्तरदाता एकल परिवार के हैं। पडेरू मंडल और चिंतापल्ली मंडल में 96 उत्तरदाता एकल परिवार से संबंधित हैं और इसी तरह मुंचिंगपुट में 95 उत्तरदाता तीनों मंडलों में कोई अधिक अंतर नहीं रखते हैं।

निष्कर्ष

आदिवासी भारत की राष्ट्रीय आबादी के सबसे पुराने जातीय समूह का गठन करते हैं, और उन्हें अक्सर ''आदिवासी'' या देश के 'मूल निवासी' के रूप में जाना जाता है। इन जनजातियों की उत्पत्ति का पता प्रोटो–ऑस्टलॉइड्स जैसी जातियों से लगाया जा सकता है, जिनके बारे में माना जाता था कि वे व्यावहारिक रूप से पूरे भारत में फैली हुई थीं। आदिवासी समुदाय सदियों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते आए हैं। अनुसूचित जनजाति संविधान द्वारा परिकल्पित एक विशेष श्रेणी है। अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में अधिसूचित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 339 के तहत गठित अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र आयोग और श्री की अध्यक्षता में। संयुक्त राष्ट्र ढाबर ने 1961 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि अनुसूचित क्षेत्रों का गठन उन्हें विकसित करने और उनमें रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों का आनंद लेने में सहायता करने के लिए किया गया था। और अबाधित।

AIRO JOURNALS

Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
National

ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

भारत में, देश की बाकी आबादी की तुलना में जनजातियाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं। आदिवासी क्षेत्र सदियों से अविकसित, उपेक्षित और यहां तक कि शेष भूमि से अलग–थलग पड़े हुए हैं। लंबे समय तक शासकों और बाद की सरकारों की लगातार उपेक्षा और उनकी विशेष समस्याओं की सराहना की कमी, अपर्याप्त निवेश और आदिवासी अर्थव्यवस्था के गैर–एकीकरण के कारण आदिवासी अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में रह रहे हैं। परिवहन, संचार और अन्य सुविधाओं के अभाव में ये मुख्य धारा से कट गए हैं। कुछ समय पहले तक उन्हें साहूकारों द्वारा वस्तुतः गुलाम बनाया गया था और बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था, जिनसे उन्होंने शानदार ब्याज दरों पर पैसा उधार लिया था और चुकाने में विफल रहे थे। जनजातीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत पिछड़ी, अविकसित और खुली और शोषित है।

<u>संदर्भ</u>

1. *अबुसलेह शरीफ, प्रबीर के, घोष, एट अल (2007), ''भारत में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक और मानव विकास प्रोफाइल'', अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद, नई दिल्ली, पीपी.83–95।*
2. *आदिनारायण रेड्डी पी, उमा देवी डी., एट अल (2010), ''ट्रिब्यूनल एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज'', सोनाली पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*
3. *आदिनारायण रेड्डी पी, उमा देवी डी., (2005), ''आदिवासी महिला शिक्षाः बाधाएं और रणनीतियाँ'', द एसोसिएटेड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।*
4. *अग्रवाल ए.एन., ''भारतीय अर्थव्यवस्था–विकास और योजना की समस्याएं'', विशा प्रकाशन, नई दिल्ली।*
5. *एजाज–उल–इस्लाम, सुलेमान कुली, और अन्य (2013) ''झारखंड के जनजातीय समुदायों के लिए वन संसाधनों का आजीविका योगदान'', इंडियन जर्नल ऑफ फंडामेंटल एंड एप्लाइड लाइफ साइंसेज, आईएसएसएनः 223 – 6345, वॉल्यूम। 3 (2), पीपी.131–144।*
6. *अजीत जायसवाल।, (2013), ''स्वास्थ्य और मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति की पोषण स्थितिः भूमिया'', ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमन सोशल साइंसेज, आईएसएसएनः 2249–460, खंड 13, अंक 1।*
7. *अलक भट्टाचार्य, वलनामुआना दारलोंग।, (2013), ''त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों के मानव विकास का पैराडिज्म'', च्।त्प्कम्प – इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, ैछः 2250–1991, पीपी। 319–324।*

ISSN:2321-3914
Volume:1 Issue 1
January 2023
Impact Factor:11.9
Subject:Humanities

8. *एलेक्जेंडर के.सी., प्रसाद आर.आर., जहांगिधर एम.पी., (1991), ''आदिवासी पुनर्वास और विकास'', रावत प्रकाशन, जयपुर, भारत।*
9. *अली ए., (2003), ''हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स इन इंडियन– एन ओवरव्यू इन डेमोग्राफिक एंड हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द ट्राइबल्स'', अनमोल पब्लिकेशंस प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली।*
10. *आलोक कुमार मीणा, (2014), ''राजस्थान में जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति'', जनजातीय स्वास्थ्य बुलेटिन, क्षेत्रीय।*

******